बीमारू से ब्रेक-थ्रू प्रदेश बना उत्तर प्रदेश

₹15 लाख करोड़ के निवेश को उतारा धरातल पर, 60 लाख युवाओं को मिला रोज़गार

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

कभी देश में बीमारू राज्य के रूप में पहचान रखने वाला उत्तर प्रदेश पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों की फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। इसकी तस्दीक पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में आए, बड़ी इंडस्ट्री के निवेश प्रस्ताव करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 8 साल में प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए, जिसमें से 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। इससे 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला। इससे 8 साल में प्रदेश का जीएसडीपी 2017 की अपेक्षा दोगुना होकर 27.51 लाख करोड़ रुपये होने जा रहा है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से उद्योगों को मिली नई रफ्तार

योगी सरकार ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को प्राथमिकता दी। औद्योगिक निवेश व रोजगार संवर्धन नीति-2017 लागू की गई, जिसके तहत निवेशकों को कर छूट, सब्सिडी और जमीन आवंटन में सहूलियत दी गई। प्रदेश मे 33 सेक्टोरल पॉलिसी लागू की गई, जिससे उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास का केंद्र बनकर उभरा। विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 2017 में 14वें स्थान पर था, जो 2022 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया।

इन परियोजनाओं ने दी नई पहचान

45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले

AI image

- डिफेंस कॉरिडोर, मेडिकल और फार्मा सेक्टर में 63,475 करोड़ रुपये के निवेश से स्वास्थ्य सेवाओं और विनिर्माण मे रोजगार बढ़ा।
- प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ-हरदोई में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क, हरदोई व कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क तथा गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर व हापुड़ में केमिकल और फार्मा पार्क निर्माणाधीन हैं।
- मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमी की मृत्यु अथवा अपंगता पर 5 लाख रुपये के सहयोग का भी प्रावधान किया गया है।
- नोएडा के बाद बीडा के रूप में बुंदेलखंड में नया औद्योगिक शहर बसाया जा रहा है। बुंदेलखंड में ड्रग व फार्मा पार्क की स्थापना का हो रहा काम।

योगी सरकार के 8 साल

इन नीतियों ने बदली निवेश की सूरत

4,674 रेग्युलेटरी कंप्लायंस बर्डन को प्रदेश में किया गया उद्योगों की सुगमता के लिए कम

500 फॉर्च्युन ग्लोबल व फॉर्च्युन इंडिया कंपनियों का प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन नीति बनी

स्वास्थ्य क्षेत्र को भी मिली बूस्टर डोज

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

साल 2017 तक यूपी में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर 80 हो गई है। इनमें 44 सरकारी और 36 निजी मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। यही नहीं आठ साल पहले यूपी में एमबीबीएस की महज 1190 सीटें थी, लेकिन आज 11 हजार 800 सीटों पर दाखिले हो रहे हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 5,250 जबकि निजी मेडिकल कॉलेजों में 6,550 सीटें हो गई हैं। इसके साथ ही केजीएमयू, पीजीआई, लोहिया संस्थान और कैंसर इंस्टिट्यूट में नए विभाग, आईआईटी कानपुर में 500 बेड वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऐंड टेक्नॉलजी की स्थापना की गई।

इस समय 2,110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और 1585 होम्योपैथी अस्पताल चल रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय और आयुष बोर्ड बनाया गया ताकि पारंपरिक चिकित्सा को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया जा सके।

सीसीटीवी की निगरानी में 974 सीएचसी

यूपी के 279 जिला अस्पतालों के बाद अब प्रदेश के सभी 974 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की भी सीसीटीवी से निगरानी होगी। होप सिस्टम के तहत इसके लिए सरकार से बजट भी जारी हो चुका है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए अब तक 207 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की गई है और दूसरे चरण के तहत 700-800 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की योजना है। यूपी में इस समय 2,200 (108 ऐंबुलेंस), 2,270 (102 ऐंबुलेंस) और 250 एयर ऐंबुलेंस की सुविधा है। हाल में सरकार ने 2,492 नई ऐंबुलेंस खरीद की कवायद शुरू की है। 72 जिलों में टीपीपी (TTP) मॉडल पर सीटी स्कैन मशीनें लगाई गई हैं।

17 से बढ़कर 80 हुए मेडिकल कॉलेज, यूपी में साल 2017 के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों का दिखने लगा असर

3,280 करोड़ रुपये की मदद दी गई सीएम विवेकाधीन कोष से 8 वर्षों मे 2 लाख 37 हजार 125 जरूरतमंदों के इलाज के लिए

एक नजर

5000 नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई

13.64 करोड़ लोगों को टेलिमेडिसिन के तहत घर बैठे डॉक्टरी परामर्श मुहैया कराया।

22681 आयुष्मान भारत हेल्थ ऐंड वेलनेस सेंटर शुरू किए गए

76% एईएस के मरीजों की संख्या में

87% जेई के मरीजों की संख्या में तक कमी आई है

58% तक घटी मलेरिया के मरीजों की संख्या

लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विवि के साथ गोरखपुर और रायबरेली में एम्स का संचालन शुरू हुआ

जेई लगभग खत्म, संक्रामक रोगों पर लगी लगाम

साल 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 30 बच्चों की मौत हो गई। सभी बच्चे वहां के इंसेफेलाइटिस वॉर्ड में भर्ती थे। योगी सरकार ने त्वरित प्रक्रिया के बाद इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन की दीर्घकालीन रणनीति पर काम किया। इंसेफेलाइटिस अब समाप्ति की ओर है। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियों ने भी इसे स्वीकार किया है। मौतों में 97% तक कमी आई है जो सरकार की अहम उपलब्धियों में से एक है। वहीं, डेंगू से होने वाली मौतों की दर 93 प्रतिशत तक कम हुई है।